(ङ) और (च) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के वर्षों के लिए गेहूं की इकनामिक लागत निम्नानुसार है:-

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	इकनामिक लागत
1992-93	504.10
1993-94	559.40
1994-95 (बजट अनुमान)	563.57

बिहार में चीनी मिलें

4277. **श्री आस मोहम्मद:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में कुल कितनी चीनी मिलें चलाई जा रही हैं;

(ख) इनमें से क्षेत्र-वार कितनी मिलें लाभ कमा रही हैं और कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं;

(ग) रुग्ण मिलों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सहकारी क्षेत्र की घाटे में चल रही चीनी मिलों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) बिहार में 30 संस्थापित चीनी मिलें हैं। इन 30 मिलों में से 15 गैर-सरकारी क्षेत्र और 15 सरकारी क्षेत्र में हैं।

(ख) यह मंत्रालय चीनी मिलों से संबंधित लाभ और घाटे का कोई हिसाब नहीं रखता है।

(ग) चीनी मिलों को पुनर्वास/आधुनिकीकरण की योजनाएं स्वयं तैयार करनी होती हैं और उनका वित्तीय संस्थाओं से अनुमोदन कराना होता है। ऐसी पुनर्वास/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि (एस॰डी॰एफ॰) से रियायती ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों को पूरा करती हों।

(घ) और (ङ) इस संबंध में नीति तैयार करना संबंधित रुग्ण चीनी मिलों/राज्य सरकारों का काम है।

Export of Foodgrains

4278. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) what is the extent of the availability of foodgrains at present in Government godowns and under what consideration Government have taken a decision to export the same;

(b) whether Government had made any assessment about the profit or loss likely to be earned or incurred from the export of wheat before taking such a decision;

(c) if so, what are the details of the assessment made in this regard;

(d) whether Government would review the proposal regarding export of foodgrains in case the money earned through such export is likely to be less than the economic cost of Food Corporation of India;

(e) whether there is any proposal under Government's consideration to sell the surplus foodgrains through Public Distribution System to poor, backward and tribal regions of the country; and

(f) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (d). The stock of foodgrains (wheat and rice) in Central Pool as on 1.7.1994 was as under:

(In lakh tonnes)

Wheat (P)	164
Rice (P)	133

(P) Provisional

No decision to export foodgrains from Central Pool has yet been taken.

(e) and (f) Already revamped Public Distribution System (RPDS) is in operation to distribute the foodgrains among the poor, backward and tribal regions of the country at a specially subsidised rate which is less by Rs. 50/- per quintal than the rate prescribed for normal PDS.

Setting up of Sugar Factories in Co- operative Sectors

4279. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether a number of cooperatives like KRIBHCO have applied for licences to set up sugar factories;

(b) if so, the number of applications received from the cooperative sector for setting up sugar factories and how many of them are pending;

(c) by when these applications will be cleared;

(d) the locations proposed for the sugar factories in the cooperative sector; and

(e) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) to (c). As on 31.7.1994, 292 applications have been received through the Department in Industrial Development for setting up of new sugar factories in the cooperative sector in the country. Of these, 282 applications have already been scrutinised by the Screening Committee. After examination, recommendaitons of the Ministry of Food were sent to the Ministry of Industry for consideration by the licensing Committee. The remaining 10 applications are still under consideration in the Ministry of Food. After their scrutiny by the screening Committee, the recommendation of the Ministry of Food inrespect of these applications will be sent for consideration by the Licensing Committee, after which letters of intent/ licences will be issued by the Ministry of Industry.

(d) and (e) A statement showing the location-wise details of the applications received through the Department of Industrial Development for setting up of new sugar factories in the co-operative sector is at Annexure [*See* Appendix 171, Annexure No. 74]

राज्यों को चीनी का वितरण

4280. **श्री नरेश यादव:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों के बीच चीनी वितरण का क्या आधार है;

(ख) क्या बिहार राज्य को अब तक वहां के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर चीनी की आपूर्ति की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय): (क) से (ग). आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के तहत अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आवंटन 1.10.1986 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए न्यूनतम 425 ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता सुनिश्चित करने के समान मानदंडों के आधार पर किया जाता है। ये मानदंड 1.2.1987 से प्रभावी हैं। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वहां की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उच्चतर स्केल पर आवंटन की अनुमति दी जा रही है। तदनुसार, पूरे देश के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए लेवी चीनी के रूप में 3.35 लाख टन चीनी.आवंटित की जा रही है। उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार प्रति वर्ष लगभग एक लाख टन चीनी त्यौहार कोटे के रूप में रिलीज करती है जो कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके मासिक लेवी आवंटन के अनुपात में आवंटित की जाती है।

उपर्युक्त के आधार पर बिहार राज्य के लिए लेवी चीनी का वर्तमान आवंटन निम्नानुसार है:-

1. मासिक लेवी चीनी कोटा : 33,459 मी. टन
2. वार्षिक त्यौहार चीनी कोटा : 10,078 मी. टन

Mid-Day meals to children

4281. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of food items served to children at mid-day meals or otherwise in Aanganwaris/Navodaya Vidyalayas/Integrated Child Development Scheme in Delhi;

(b) where from these food items are purchased and what is the procedure followed in the purchase thereof itemwise;

(c) the quantity, item-wise, given to the children per day, institution-wise;

(d) how much worth of rupees of these items purchased in each of the last three years, year-wise and from where;

(e) the number of food samples lifted for testing and how many of them were found adulterated or substandard, item-wise, and what action was taken thereon;

(f) the reasons for not buying these food stuff from the Kendriya Bhandar and whether